एक्शन मोड में शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष

डॉ. राजेश शर्मा ने सीएम सुक्खू को सौंपा सुधारों का 'ब्लूप्रिंट'

अनंत ज्ञान

ब्यूरो धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात को प्रदेश की आगामी शैक्षिक नीतियों और बोर्ड की कार्यप्रणाली में होने वाले बड़े बदलावों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस विस्तृत चर्चा में डॉ. शर्मा ने शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन साझा किया। वहीं, मुलाकात के दौरान डॉ. राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बोर्ड द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया को सटीक करने और परिणामों को समयबद्ध घोषित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा बोर्ड के इन प्रयासों की सराहना की और छात्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के निर्देश दिए।

शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा मुख्यमंत्री सुक्खू से शिष्टाचार भेंट करते हुए। अनंत ज्ञान

डिजिटलाइजेशन और 'डोर स्टेप' सर्विस पर जोर

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बोर्ड अध्यक्ष को निर्देशित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में बोर्ड की सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और 'यूजर-फ्रेंडली' बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को प्रमाण पत्र, माइग्रेशन या अन्य सुधारों के लिए धर्मशाला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार अनिवार्य है। बोर्ड अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि बोर्ड जल्द ही कई सेवाओं को 'वन-क्लिक' पर उपलब्ध कराने जा रहा है।

परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजामों को लेकर भी की चर्चा

बैठक में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजामों को लेकर भी चर्चा हुई। डॉ. राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि शिक्षा बोर्ड नई शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों को धरातल पर उतारने और प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मंच प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बोर्ड की कार्यप्रणाली में कुछ बड़े और छात्र-हितैषी फैसले देखने को मिल सकते हैं।

पंजाब केसरी
THU,12 FEBRUARY 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 4

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने सी.एम. सुक्खू को सौंपा बोर्ड में सुधारों का ब्लूप्रिंट

बोर्ड परीक्षाओं और डिजिटल बदलावों पर मुख्यमंत्री से मिली हरी झंडी

धर्मशाला, 11 फरवरी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात को प्रदेश की आगामी शैक्षिक नीतियों और बोर्ड की कार्यप्रणाली में होने वाले बड़े बदलावों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री के साथ हुई इस विस्तृत चर्चा में डा. राजेश ने शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन सांझा किया। मुलाकात के दौरान डा. राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बोर्ड द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों से अवगत करवाया।

उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया को सटीक करने और परिणामों को समयबद्ध घोषित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा बोर्ड के इन प्रयासों की सराहना की और छात्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के निर्देश दिए।

धर्मशाला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा। (ब्यूरो)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोर्ड अध्यक्ष को निर्देशित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में बोर्ड की सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और यूजर फ्रैंडली बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को प्रमाण पत्र, माइग्रेशन या अन्य सुधारों के लिए धर्मशाला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार अनिवार्य है। बोर्ड अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि बोर्ड जल्द ही कई सेवाओं को वन क्लिक पर उपलब्ध करवाने जा रहा है। बैठक में आगामी बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजामों को लेकर भी चर्चा हुई।

Apka Faisla 12-02-2026

स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम को सौंपा सुधारों का ब्लूप्रिंट

धर्मशाला,(आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात को प्रदेश की आगामी शैक्षिक नीतियों और बोर्ड की कार्यप्रणाली में होने वाले बड़े बदलावों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस विस्तृत चर्चा में डॉ. शर्मा ने शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन साझा किया। मुलाकात के दौरान डॉ. राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बोर्ड द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया को सटीक करने और परिणामों को समयबद्ध घोषित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा बोर्ड के इन प्रयासों की सराहना की और छात्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोर्ड अध्यक्ष को निर्देशित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में बोर्ड की सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली बनाया जाए।

Dainik Jagran 12-02-2026

डा. राजेश ने मुख्यमंत्री सुक्खू को सौंपा सुधारों का ब्लूप्रिंट

जागरण संवाद केंद्र, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से भेंट की। मुलाकात को आगामी शैक्षिक नीतियों और बोर्ड की कार्यप्रणाली में होने वाले बदलावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान डा. शर्मा ने शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन साझा किया।

डा. राजेश नई दिल्ली में सीएम सुक्खू से शिष्टाचार भेंट करते हुए ● जागरण

डा. राजेश ने सुक्खू को बोर्ड की ओर से हाल ही में शुरू किए नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों से अवगत करवाया। बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया को सटीक करने व परिणामों को समयबद्ध घोषित करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को निर्देश दिए कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में बोर्ड की सेवाओं को डिजिटल और 'यूजर-फ्रेंडली' बनाया जाए। दूरदराज क्षेत्रों के बच्चों को प्रमाणपत्र, माइग्रेशन या अन्य सुधारों के लिए धर्मशाला के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए आनलाइन सेवाओं का विस्तार अनिवार्य है। अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि बोर्ड जल्द कई सेवाओं को 'वन-क्लिक' पर उपलब्ध कराने जा रहा है।

बैठक में बोर्ड परीक्षाओं के संचालन, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों पर इंतजामों को लेकर चर्चा हुई। डा. राजेश ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि बोर्ड नई शिक्षा नीति के प्रविधानों को धरातल पर उतारने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Amar Ujala 12-02-2026

सरकारी सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों की स्क्रीनिंग 22 मार्च को

प्रिंसिपलों के 134 पदों के साथ 5,623 पद भरने के लिए होगी परीक्षा

अमर उजाला ब्यूरो

धर्मशाला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने वाले शिक्षकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 22 मार्च को होगा। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है।

इस दौरान शिक्षा बोर्ड प्रिंसिपलों के 134 पदों के साथ 5,623 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आरएंडपी नियमों को पूरा करने वाले शिक्षक 24 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से 500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूबे के 134 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में तब्दील किया है। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के तहत यह परीक्षा निदेशालय विद्यालय शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत सेवारत शिक्षकों में से उन शिक्षकों के लिए होगी, जो लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित आवश्यक योग्याजाएं एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते होंगे।

ऑनलाइन माध्यम से 24 फरवरी तक 500 रुपये शुल्क के साथ होगा आवेदन

इस स्क्रीनिंग टेस्ट में शिक्षा बोर्ड की भूमिका टेस्ट के आयोजन, पदवार मेरिट सूची तैयार करने और परिणाम घोषित करने तक रहेगी, जबकि पात्रता निर्धारण, प्रतिनियुक्ति, पदस्थापना एवं सेवा संबंधित सभी विषय निदेशालय विद्यालय शिक्षा हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि पात्र शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से 24 फरवरी तक 500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। वहीं 25 से 27 फरवरी 600 रुपये लेटफीस के साथ कर सकेंगे, जबकि आवेदनों पत्रों में संशोधन के लिए 28 फरवरी से एक मार्च तक का समय रहेगा।

ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य माध्यमों, बिना फीस और आधे अधूरे प्राप्त होने वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई से संबंद्ध करने जा रही है।

इतने भरे जाएंगे पद

प्रिंसिपल के 134, लेक्चरर बॉयोलॉजी के 150, लेक्चरर कैमिस्ट्री के 161, लेक्चरर फिजिक्स के 161, लेक्चरर गणित के 160, लेक्चरर कॉमर्स के 288, लेक्चरर इकोनोमिक्स के 167, लेक्चरर इंग्लिश के 384, लेक्चरर राजनीति शास्त्र के 182, लेक्चरर इतिहास के 182, लेक्चरर हिंदी के 182, लेक्चरर ज्योग्राफी के 134, लेक्चरर सोशोलॉजी के 134, लेक्चरर संस्कृत के 134, लेक्चरर म्यूजिक के 134, लेक्चरर आईपी के 134, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के 134, लेक्चरर सायकोलॉजी के 134, डीपीई के 140, टीजीटी आर्ट्स के 480, टीजीटी मेडिकल 244, टीजीटी नॉन मेडिकल के 244, शास्त्री के 221, लैंग्वेज टीचर के 239, ड्राइंग मास्टर के 179, फिजिकल एजुकेशन टीचर के 147 और जेबीटी के 640 पद भरे जाएंगे।

Divya Himachal 12-02-2026

तैयारी दसवीं और जमा दो पास विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, 11 मार्च तक करें आवेदन

मेधावी-जरूरतमंद छात्रों को मिलेगी डाक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति

सिटी रिपोर्टर- धर्मशाला

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पिछले साल मार्च 2025 में आयोजित दसवी और जमा-दो की नियमित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए डा. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति' योजना के तहत बुधवार को आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत दोनों कक्षाओं के 14-14 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र, सहमति पत्र और बिल प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि विद्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या मुखिया से सत्यापित करवाकर 11 मार्च 2026 तक बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे। साथ ही निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। शिक्षा बोर्ड के अनुसार छात्रवृत्ति का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। इस योजना के तहत 90 प्रतिशत छात्रवृत्तियां मेरिट और आय के आधार पर प्रदान की जाएंगी। इस योजना में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं, ताकि बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। वहीं दस प्रतिशत छात्रवृत्ति दिव्यांग श्रेणी के उन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है, जिन्होंने 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस योजना छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा के लिए 27 सौ रुपए वार्षिक तथा जमा-दो कक्षा के लिए तीन हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी या अभिभावक गलत जानकारी देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, तो उससे 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि वापस वसूली जाएगी।

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष बोले, योजना का लाभ उठाएं छात्र

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य प्रदेश के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करना है। डा. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। डा. शर्मा ने विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने तथा समय पर आवेदन करने का आग्रह किया। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों से भी अपील की कि वे पात्र छात्रों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें।

Divya Himachal 12-02-2026

डीएलएड की 205 सीटें अभी भी खाली

सिटी रिपोर्टर- धर्मशाला

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2025 से 27 के लिए डीएलएड के निजी शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटें भरने हेतु दूसरे चरण के दूसरे राउंड की काउंसिलिंग बुधवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। बता दें कि दूसरे राउंड की कांउसिलिंग का आज अंतिम दिन है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के 27 निजी कालेजों में कुल 205 सीटें खाली रह गई हैं। बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इन रिक्त सीटों में 55 सब्सिडाइज्ड और 150 नॉन-सब्सिडाइज्ड सीटें शामिल हैं। इससे साफ तौर पर सामने आया है कि अभ्यर्थियों का झुकाव कम फीस वाली अनुदानित सीटों की ओर अधिक रहा, जबकि अधिक शुल्क वाली गैर-अनुदानित सीटों पर छात्रों ने अपेक्षाकृत कम रुचि दिखाई। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड का प्रयास रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक प्रशिक्षण का अवसर मिल सके। इसी उद्देश्य से मेरिट के आधार पर काउंसलिंग आयोजित की गई और दूसरे चरण में न्यूनतम अंकों की सीमा में भी छूट दी गई । शेष बची सीटों को लेकर बोर्ड नियमानुसार आगामी निर्णय लेगा, जिससे शैक्षणिक सत्र समय पर सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। कांगड़ा जिले के केएलबी डीएवी कॉलेज पालमपुर और सिरमौर के एचपी कॉलेज काला अंब में भी कई सीटें खाली पाई गई हैं। वहीं शिमला जिले के कॉलेजों में अनुदानित सीटों पर प्रवेश लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन गैर-अनुदानित सीटों पर अभी भी कुछ सीटें खाली बनी हुई हैं, जिन्हें भरने के लिए बोर्ड आगे की रणनीति तय करेगा।

Divya Himachal
12-02-2026

एसओएस परीक्षा के लिए आठ नए केंद्र स्थापित

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 में आयोजित होने वाली एसओएस परीक्षाओं को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आठ नए सरकारी एवं निजी अध्ययन केंद्रों को परीक्षा केंद्र के रूप में बुधवार को स्थापित किया है। बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन नए परीक्षा केंद्रों को चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में बनाया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को अपने नजदीकी क्षेत्रों में परीक्षा देने की सुविधा मिल सकेगी। इन केंद्रों में 100 लेकर 600 छात्रों तक बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।